MR. DEPUTY-SPEAKER : How can he give it ? That is not there. Why can't he request Dr. Subramaniam Swamy to give a letter separately ? He cannot give it on behalf of all. I am saying that I will permit every hon. member provided they give it in writing. I do not want to go into the reasons as to why they were absent. But does not any hon. member feel that, when the Chair calls him and he is not present in the House, it is a disrespect to the Chair ?

(*Interruptions*)**

SHRI MANI RAM BAGRI : I am on a point of order.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 2.05 P.M.

13.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Five minutes past Fourteen of the clock.

14.09 hrs.

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Nine Minutes past Fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377—*Contd.*

(ii) Construction of more houses for Workers of Ordnance Factories at Jabalpur

श्री बाबू राव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में जबलपुर जनसंख्या की दृष्टि से क्रमांक दो नम्बर का शहर है तथा आज जनसंख्या साढ़े दस लाख है। मध्य प्रदेश में यह एक मात्र नगर है जहां दो विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय, विद्युत मंडल का मुख्यालय, डाक तार विभाग का कारखाना तथा प्रशिक्षण केन्द्र है। शिक्षा की दृष्टि से जबलपुर नगर मध्य प्रदेश में क्रमांक एक पर है तथा एक लाख से अधिक विद्यार्थी वहां पर शिक्षारत हैं।

भौगोलिक दृष्टि से, जबलपुर जिले में भारत का मध्य बिन्दु है। सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्तता के कारण रक्षा मंत्रालय ने अनेकों कारखाने यहां खोले हैं। अनुमानत: 65,000 कर्मचारी इनमें कार्यरत हैं। 35 प्रतिशत आवास गृह कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का विभागीय नियम है। परन्तु जबलपुर में मात्र 16 प्रतिशत कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है।

जबलपुर में स्थानाभाव होने के कारण मकानों के किराये बहुत बढ़े हैं, एक कमरा सौ रुपये से कम में नहीं मिलता।

अतएव रक्षामन्त्री जी से अनुरोध है कि अविलम्ब जबलपुर में आवश्यक मात्रा में गृह निर्माण के आदेश प्रदान करें जिससे कि 35 प्रतिशत के नियम पर अमल हो।

(iii) Funds for roads in Orissa

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Out of 46,992 inhabited villages of Orissa State, only 1,242 villages have been connected by all-weather roads as on 31.3.1983 although, it has been the avowed policy of the Central Government for linking up of all villages with a population of 1,500 and above and 50 per cent of the villages with population of 1,000 and 1,500 by 1990. Similarly, the total percentage of surfaced roads to the total road length of the State is only 28.0 against the all-India average of 40.6 per cent. There are still Sub-Divisional and Block headquarters of the State not being linked up by pucca roads with the District headquarters.

Under the Minimum Needs Programme and now under the NREP, the Government at the Centre aimed at removing the distortions in different States by providing enough funds to have all-weather roads to link up the villages and the local administrative units of the State.

Therefore, it is imperative on the part of the Centre to see that the Block machinery

**Not recorded.

is strengthened with adequate staff especially with a network of engineering expertise and back up of funds to help preserve the assets and achieving the targets envisaged in the Sixth Five Year Plan in this sphere of work.

(iv) Demand to declare people of Vimukta Jati (Tapriwas) as Scheduled Tribes

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, 8 करोड़ विमुक्त जाति के लोग भारत में रहते हैं। अरसे से मांग कर रहे हैं कि उनको विमुक्त जाति करार दिया जाए क्योंकि हरिजन जाति के उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। ये विमुक्त जातियां हैं राय, बाजीगर, गड़रिया, सिक्लीगर, अहेड़ी, नायक, कूचिया सांसी, बावरिया इत्यादि। ये 193 जातियां हैं पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 नवम्बर, 1982 को इनके हक में फैसला दिया कि इनको विमुक्त जाति में शामिल किया जाय। लेकिन यह फैसला अभी तक लागू नहीं किया गया है। अखिल भारतीय टपरीवासी संघ ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री से बार-बार इसके लिए मुलाकात की और उन्होंने उनको विश्वास भी दिलाया, परन्तु अभी तक उनकी मांग मानी नहीं गई है जिसके लिए अब वह संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं और वोट क्लब पर धरना व भूख हड़ताल दे रखा है।

यह सरकार का धर्म है कि वह तुरन्त इनको मांगों को स्वीकार करे और इनको विमुक्त जाति में शामिल कर के राहत दे।

(v) Non-use of Hindi in Writing names of roads etc. in Hyderabad and Secunderabad

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष जी, इन दिनों आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद तथा सिकन्द्राबाद की सड़कों तथा गलियों में लगे हुए बोर्डों पर नगर निगम नये सिरे से मोहल्लों तथा बाजारों के नाम लिखवा रही है। यह पहला अवसर है जबकि आन्ध्र प्रदेश के मोहल्ला सूचक फलकों से हिन्दी गायब की गई है। केवल तेलगू, अंग्रेजी और उर्दू का उपयोग किया जा रहा है। हैदराबाद नगर निगम आरम्भ से साइन बोर्डों पर ही नहीं, अपने सभी कार्यों में हिन्दी का उपयोग करता रहा है। जब निगम जन प्रतिनिधियों के हाथ में था, हिन्दी भाषी सदस्यों को बैठकों का विवरण भी हिन्दी में मिलता था। शहर में सात लाख से अधिक हिन्दी भाषी बसते हैं।

यही नहीं, शहर में दिखाई जाने वाली हिन्दी फिल्मों के साइन बोर्डों से भी हिन्दी गायब कर दी गई है और इसी प्रकार सभी स्थानों पर, जहां हिन्दी में नाम लिखे हुए थे, उनको मिटा दिया गया है।

श्रीमान्, यह बड़ी भयावह स्थिति है जिसके कारण हिन्दी भाषी लोगों में बड़ा रोष और असन्तोष व्याप्त है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके हिन्दी को अपना सम्मानपूर्ण यथास्थान दिलाए।

(vi) Special Postal Stamp to Commemorate the fourteen hundred Birth Centenary of Hazrat Imam Hussain

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : The 14 hundred birth Centenary of Hazrat Imam Hussain comes off on May 5, 1984. Everybody is aware that Imam Hussain made the supreme sacrifice in the fields of Karbala for the sake of justice and truth. He is remembered by mankind for his preaching of universal brotherhood and human values.

On the occasion of the 14th hundred Birth Centenary of Hazrat Imam Hussain, the Central Government should issue a Special Postal Stamp to commemorate his memory and sacrifice for human kind. Of course, this gesture of the Government will cement the unity of people believing in all religions and make the bonds of secularism more strong.

I would urge the Government to consider this proposal with all seriousness and do the needful for issuing special postal stamps in his name.